भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 802

जिसका उत्तर दिनांक 09.02.2023 को दिया जाना है

ऊर्जा आवश्यकताओं के विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा

802 श्री पी. विल्सन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्यम और लघु उद्योगों में ऊर्जा आवश्यकताओं के विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति/ढांचा तैयार किया है;

(ख) क्या सरकार की अपनी स्वच्छ ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के लिए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र से भागीदारी आमंत्रित करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क), (ख) व (ग) वर्तमान नीति परमाणु ऊर्जा को निषिद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में रखती है। भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 2015 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन किया है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संयुक्त उद्यम सक्षम हो सके।

* * * * *